

सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:

सरकारी कॉलेजों में सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण से संबंधित मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कॉलेजों में वर्ष 2020-21 के लिये सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों (Doctorate of Medicine/DM and Master of Chirugiae/M. Ch.) में दिये जा रहे 50% इन-सर्विस आरक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

प्रमुख बंदि

- अगस्त 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को इन-सर्विस डॉक्टरों को [राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा \(NEET\)](#) [स्नातकोत्तर \(PG\) डिग्री पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण](#) का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी।
- नरिणय में कहा गया कि राज्य को [सूची-III की प्रवर्षिटा 25](#) के तहत स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिये प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की शक्ति प्राप्ता है।
 - [सूची-III की प्रवर्षिटा संख्या 25](#): शक्ति (तकनीकी शक्ति, चकित्सा शक्ति और विश्वविद्यालयों सहित) संबंधी प्रावधान प्रवर्षिटा संख्या 63, 64, 65 के वषिय हैं।
 - संवधान संघ और राज्यों के बीच वधायी वषियों को [सातवी अनुसूची](#) के तहत तीन स्तरों पर वभाजति करता है, जो सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) में वर्णति हैं।
- नवंबर 2020 में, तमलिनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर-स्पेशलिटी सीटों के लिये राज्य के इन-सर्विस उम्मीदवारों की काउंसलिंग कर इसे भरने की अनुमति दी।
 - ये सीटें उन उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी जो [NEET- सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम \(SS\)](#) में सफल हुए हों। इसके लिये [चकित्सा शक्ति नदिशालय की चयन समति](#) भेरटि सूची तैयार करेगी और काउंसलिंग आयोजति करेगी।
 - राज्य सरकार ने यह तर्क दया है कि चकित्सा शक्ति और व्यवहार में [सुपर-स्पेशलाइज्ड योग्य डॉक्टरों की अत्यंत आवश्यकता](#) थी।
 - DM/M. Ch. पाठ्यक्रमों में 50% सीटें इन-सर्विस उम्मीदवारों को आवंति कये जाने के बाद शेष सीटों को [स्वास्थ्य सेवा महानदिशालय \(DGHS\)](#) को सौंप दया जाएगा।
 - DGHS सार्वजनिक स्वास्थ्य, चकित्सा शक्ति और स्वास्थ्य देख-भाल से संबंधति तकनीकी ज्ञान का भंडार है। यह [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न संगठन](#) है।
- डॉक्टरों सहति NEET 2020 में सफल होने वाले PG धारकों ने इस नरिणय को चुनौती देते हुए कहा कि सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये कसि भी प्रकार के आरक्षण की कोई अवधारणा वदियमान नहीं है।
 - नरिणय को चुनौती देने वाले डॉक्टरों ने [प्रीति शरीवासत्व \(डॉ.\) बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1999](#) मामले में दये गए फैसले का उल्लेख कया जसिमें यह माना गया था कि ["योग्यता और केवल योग्यता ही सुपर-स्पेशलिटी स्तर पर प्रवेश का आधार है"](#)।
- उनके द्वारा की गई अपील में तर्क तर्क दया गया कि राज्य का आदेश [2019 के स्नातकोत्तर चकित्सा शक्ति \(संशोधन\) वनियमों \(Postgraduate Medical Education \(Amendment\) Regulations of 2019\)](#) के वषिरीत था, जसिमें यह कहा गया था कि DGHS को प्रवेश प्रकरया का प्रभारी होना चाहये।
 - ये वनियम केंद्र और राज्य सरकारों के [सभी चकित्सा शक्ति संस्थानों, डीमड विश्वविद्यालयों तथा नगर नकियों एवं न्यासों आदि द्वारा स्थापति चकित्सा शक्ति संस्थानों](#) में सभी सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिये काउंसलिंग आयोजति कराने हेतु [DGHS को सशक्त बनाते हैं](#)।

स्रोत: द हट्टू

